(घ) क्या राज्य सरकार ने किसी वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी से इसकी जांच करायी है; और

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) रणथम्भौर बाघ रिजर्व में चोरी-छिपे शिकार करने के कुछ प्रमाण मिले हैं किन्तु उनकी वास्तविक संख्या अभी ज्ञात नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जांच के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(1) 1992 की गणना को उस समय विद्यमान अड़चनों के कारण प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । लगातार निगरानी करके तथा वन कर्मचारियों और बाहर के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से की गई गणना से ही बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सकता है ।

(2) चोरी छिपे शिकार के कुछ प्रमाण मिले हैं, जिनकी संख्या पुलिस जांच पूर्ण होने के बाद ही उपलब्ध होगी ।

(3) इसमें किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है अपितु प्रशासनिक ढांचे तथा क्षेत्र में विद्यमान प्रणाली को मुख्यतः दोषी माना गया है।

उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ जल प्रदूषण

3582. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जल प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण हैं और किन-किन स्थानों पर जल प्रदूषण फैल रहा है; और

(ग) सरकार ने जल प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) अशोधित मलजल तथा औद्योगिक बहिस्रावों के बहाव से उत्पन्न जल प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश के शहरों में सतही जल की गुणवत्ता का स्तर निर्धारित मानकों से कम हो गया है । इन बहिस्रावों में अभी भी वृद्धि हो रही है ।

(ग) जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं ।

(2) उद्योगों के स्थान-निर्धारण तथा संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं ।

(3) उद्योगों को कहा गया है कि बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अंदर रखने के लिए वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें ।

(4) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानकों के पालन के लिए प्रदूषक उद्योगों के लिए एक कार्य योजना तैयार की है ।

(5) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने, प्रदूषक उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।

(6) परिवेशी वायु गुणवत्ता एवं परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया।

(7) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(8) जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।

(9) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में प्रदूषण शोधन प्रणालियां स्थापित करने और उनके उन्नयन के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

(10) गंगा की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गंगा कार्य योजना के तहत एक विशेष परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत इलाहाबाद, फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़, हरिद्वार, कानपुर, मिर्जापुर और वाराणसी में मलजल के शोधन के लिए मलजल तथा मल-निकास प्रणालियों के निर्माण/संवर्धन की स्कीम शुरू की गई है।

"Clearance to Power Projects"

3583. SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is considerable delay in giving clearance to as many as 33 power projects in various states causing undue delay in their implementation; and

(b) if so, the reasons thereof and the proposals of Government propose to take ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) No, Sir, Only eighteen power projects presently await clearance from environment and forestry angles due to non-submission of requisite data, Management Plan and scheme for compensatory afforestation by the project authorities and State Governments. Many of these projects have been referred to the Ministry for consideration from December, 1992 onwards.

Fishing Jetty at Talchua in Orissa

3584. SHRI KAMAL MORARKA : SHRIMATI KAMLA SINHA : MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the Orissa Government's plan to set up a fishing jetty at Talchua in Orissa;

(b) if so, the details thereof, and

(c) whether any assurance is being sought on the safety and protection of the Olive Ridley turtles, identified as an endangered species ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) :

(a) Government has seen Press reports in this regard.

(b) Details of the project have been called for from the Government of Orissa.

(c) Protection of all endangered species will be ensured while approving the project if requiring clearance of this Ministry.

African lions in the Shakkar-Baug Zoo in Junagarh

3585. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of ENVIRON-